उज्जैन, बुरहानपुर में शिक्षकों को मान लिया कर्मवीर योद्धा

अब अन्य जिलों में भी शिक्षकों ने उठाई मांग इसी तरह जारी किए जाएं आदेश

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

उज्जैन एवं बुरहानपुर से प्रदेश के शिक्षकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। यहां पर कलेक्टर ने शिक्षकों को कोरोना योद्धा का दर्जा देते हुए आदेश जारी किए हैं। इन जिलों में आदेश होते ही अब अन्य जगहों पर शिक्षकों ने अपनी जिलाधिकारियों पर यह लाभ देने के लिए प्रबलता से दबाव बनाया है। शासकीय अध्यापक संगठन ने मुख्यमंत्री कोविड.19 यौद्धा कल्याण योजना के तहत राजधानी भोपाल में कोरोना महामारी में विभिन्न कार्यो में ड्यूटी कर रहे शिक्षक अध्यापकों को अन्य जिलों की भांति भोपाल में भी कोरोना यौद्धा का दर्जा देने की मांग कलेक्टर से की है।

संगठन के प्रदेश संयोजक उपेन्द्र कौशल ने बताया है कि कोरोना महामारी से प्रदेश में 400 से अधिक शिक्षक काल को समा गये। वही लगभग 5000 शिक्षक कर्मचारी कोरोना बीमारी के शिकार है। राजधानी भोपाल में ही अभी तक 10 शिक्षकों की मृत्यु हो चुकी है और 300 से अधिक शिक्षक कोरोना की चपेट में है। संगठन ने कलेक्टर भोपाल से मांग की है कि शासन की कोरोना यौद्धा योजना में कम से कम उन शिक्षकों को ही शामिल कर लिया जाए जोकि कोरोना महामारी से सबंधित ड्यूटी में जिनसे कार्य लिया जा रहा है।

संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश दुबे का कहना है कि शिक्षकों से अनेक कार्य करवाए जा रहे हैं। स्थिति ऐसी है कि शिक्षकों से कोरोना महामारी में कार्य तो स्वास्थ्यए राजस्वए स्थानीय निकाय इत्यादि कर्मचारियों के समान कार्य कराया जा रहा है लेकिन शासन से प्राप्त सुविधाएं इन शिक्षकों को कोई भी प्रदान नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन एवं बुरहानपुर की तरह है प्रदेश के समस्त जिलों में कलेक्टरों को तत्काल शिक्षकों को करुणा योद्धा के आदेश जारी करना चाहिए।

प्रदेश में शिक्षकों को मिलेगी बड़ी राहत

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत कुमार शर्मा ने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार उज्जैन और बुरहानपुर कलेक्टर ने शिक्षकों के लिए पूर्व में युद्ध के आदेश जारी किए हैं। उसी तरह की व्यवस्था पूरे मध्यप्रदेश में हो। इस प्रकार का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जाना चाहिए। ताकि कलेक्टर अपने.अपने जिलों में शिक्षकों को यह लाभ दे सकें।

अस्पतालों के नजदीक हो मेडिकल स्टाफ के ठहरने की व्यवस्था

स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कहा कि पिछले साल राज्य सरकार ने किए थे प्रबंध

भोपाल। सरकारी अस्पतालों में उपचार कर रहे मेडिकल स्टाफकी आवास संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों ने राज्य सरकार को कीमती सुझाव दिए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले साल जिस प्रकार ठहरने के प्रबंध होटलों में बनाए गए थे। राज्य सरकार को वैसे ही व्यवस्था करना चाहिए।

स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि रात्रि कालीन जो मेडिकल स्टाफ ड्यूटी कर रहा है। उसे प्रतिदिन अनेक प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देर रात्रि ड्यूटी से छूटने के बाद कर्मचारी बड़ी परेशानी उठाकर घर पहुंचते हैं। इसके बाद उन्हें पूरी तरह सैनिटाइज होना पड़ता है। खासकर महिला कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि जिनके छोटे बच्चे हैं। उनके लिए सबसे ज्यादा मुसीबत है। सरकार को सुझाव दिए गए हैं कि जिस प्रकार पिछले वर्ष अस्पतालों के नजदीक होटलों में मेडिकल स्टाफ के ठहरने की व्यवस्था बनाई गई थी। ठीक उसी प्रकार के प्रबंध इस बार भी किए जाएं। ताकि कर्मचारी स्वयं सुरक्षित रख रहे और अपने परिवार को भी संक्रमण से बचा सके।

तत्काल करना चाहिए सरकार को यह व्यवस्था

मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष कुमार नागर का कहना है कि राज्य सरकार को तत्काल यह व्यवस्था कर देना चाहिए। क्योंकि जो मेडिकल स्टाफअस्पताल में ड्यूटी करता है। उनके घरों में सबसे अधिक संक्रमण फैल रहा है। सरकार को इस विषय पर विचार करके तत्काल ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। मेडिकल स्टाफ जब परिवार से दूर रहेगा तो निश्चित तौर पर संक्रमण भी कम होगा।

अधिकृत व्यवस्था कर हो सकता समस्या का समाधान

मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष अनिल एडविन का कहना है कि पूर्व की तरह अस्पतालों के आस पास की होटलों को अधिकृत कर इस समस्या का निदान किया जा सकता है। ड्यूटी से छूटने के बाद मेडिकल स्टाफ वहां जाकर रुके। उनके भोजन की व्यवस्था वहां हो। ताकि वे निश्चिंत होकर अपनी ड्यूटी कर सके एवं उनके परिवार भी संक्रमित होने से बच सकें। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तत्काल इस संबंध में आदेश जारी करना चाहिए।

Badri Gautam

उज्जैन में कलेक्टर ने शुक्रवार को निकाला कोरोना योद्धा का आदेश, विभाग कह रहा पहले से शामिल

उज्जैन| कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को आदेश निकाला कि कोविड-19 में उनकी सक्रिय भूमिका और एक्सपोजर को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, लिपिकीय अमले, प्राचार्य, शिक्षक के साथ संविदा कर्मी व भृत्यों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का पात्र माना जाएगा। जबकि विभाग कह रहा है कि उन्हें पहले से ही इस योजना में शामिल किया गया है। शेष | पेज 5 पर

शिक्षकों समेत जो भी कर्मचारी, अधिकारी कोरोना ड्यूटी कर रहे हैं वे सभी कोरोना वॉरियर्स हैं : भोपाल।

स्कूल शिक्षा विभाग के टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ समेत अन्य विभागों के कर्मचारी जो कोरोना संबंधी ड्यूटी कर रहे हैं वे मुख्यमंत्री कोरोना योद्धा में शामिल माने जाएंगे। सामान्य प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि पिछले साल भी इस बारे में आदेश निकला था। अभी भी आदेश जारी किया गया है। यह 2 महीने की समय अवधि के लिए रहेगा। पिछले साल भी इस बारे में आदेश जारी किया गया था। कोरोना संबंधी किट वितरण, सर्वे, सेंपलिंग, अस्पतालों में, कंट्रोल रूम में जहां भी जिनकी ड्यूटी लगी

Badri Gautam

शिक्षा विभाग ने कहा- कोरोना से 441 मौत, पोर्टल बता रहा अप्रैल में ही 419

भास्कर न्यूज भोपाल | स्कूल शिक्षा विभाग विभाग का कहना है कि कोरोना संक्रमण से एक साल में 441 मौत हुई है। इसके अलावा 234 अन्य मौत बीमारियों व दुर्घटनाओं से हुई है। विभाग ने यह भी कहा कि जिनकी कोरोना के कारण मौत हुई है, वे कोरोना की ड्यूटी में नहीं थे। इधर, विभाग का ही विमर्श पोर्टल बता रहा है कि 2934 संक्रमित हुए हैं और 786 मौत हुई है। पोर्टल के अनुसार अप्रैल में ही कोरोना से 419 मौत हुई है। इसके अलावा अप्रैल में ही 133 मौतें और हुई हैं, लेकिन पोर्टल पर इसकी वजह नहीं लिखी गई है। इस बीच जिस छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा कोरोना से मौत हुई है, वहां आंकड़ा 22 मार्च 2021 से 28 अप्रैल 2021 तक 87 हो गया है। भास्कर के पास छिंदवाड़ा में मरने वालों की पूरी सूची है। इसीके साथ विमर्श पोर्टल का ताजा स्क्रीन शॉट भी है। इसके अलावा जिलेवार संक्रमित व निधन की जानकारी भी सूची अनुसार है।

उज्जैन में कलेक्टर ने आज निकाला कोरोना योद्धा का आदेश, विभाग कह रहा पहले से शामिल : उज्जैन में कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को आदेश निकाला कि कोविड-19 में उनकी सक्रिय भूमिका और एक्सपोजर को देखते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, लिपिकीय अमले, प्राचार्य, शिक्षक के साथ संविदा कर्मी व भृत्यों को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना का पात्र माना जाएगा। जबकि विभाग कह रहा है कि उन्हें पहले से ही इस योजना में शामिल किया गया है।

Badri Gautam

बढ़ रहा शिक्षकों की मौत का ग्राफ, लापरवाही का आरोप

कोरोना वॉरियर घोषित किए जाने की मांग

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल

मो.नं. 9893231237

प्रदेश में शिक्षकों के साथ ही गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की मौत का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। आज तक प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शिक्षक, लिपिक वर्ग, प्राचार्य, अधिकारी समेत लगभग 716 से अधिक की मौत हो चुकी है।

यह आंकड़ा मप्र शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता एवं भोपाल जिला अध्यक्ष सुभाष सक्सेना मीडिया को देते हुए शासन-प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सक्सेना ने कहा कि शिक्षकों और स्कूल शिक्षा विभाग के गैर शैक्षणिक कर्मचारियों व अधिकारियों को बिना किसी ट्रेनिंग व सुरक्षा के कोरोना ड्यूटी में लगा दिया गया है। इस लापरवाही के कारण इनकी असमय मौत हो रही है। मरने वालों में से अधिकांश शिक्षकों की ड्यूटी के चलते कोरोनावायरस से संक्रमित होकर मौत हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा समस्त विभागों के कर्मचारियों को शिक्षकों को कोरोना वॉरियर घोषित किया जाकर 50 लाख रुपए की राशि दिए जाने के आदेश दिए गए हैं, परंतु अभी तक किसी भी शिक्षक को 50 लाख की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। संगठन का अनुरोध है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी दिवंगत हुए हैं। उनके आश्रित परिवार को शीघ्र 50 लाख की राशि दी जाए एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण किया जाकर नियुक्ति प्रदान की जाए।

Badri Gautam

शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए

प्रांतीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

दतिया, ब्यूरो। शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा घोषित करने के लिए प्रांतीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधीश को ई-मेल के माध्यम से ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में जिलाध्यक्ष बलराम शर्मा, प्रांत उपाध्यक्ष आलोक गोस्वामी, महासचिव नीरज श्रीवास्तव, विकास शुक्ला, महेन्द्र मुडिआ ने बताया कि जिले के सभी विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी किसी न किसी रूप में लगाई जा रही

है। इनमें शिक्षक संवर्ग की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षकों की डयूटी कोविड के लिए लगाई जा रही है। इस बावत उज्जैन एवं राजगढ़ जिलों में शिक्षकों को अग्रिम पंक्ति योद्धा के आदेश जारी किये जा चुके हैं। आपसे अनुरोध है कि शिक्षक संवर्ग को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। सभी शिक्षक संवर्ग का प्राथमिकता के आधार पर वेक्सीनेशन कराने हेतु आदेश जारी करें।

Badri Gaur

अब शिक्षकों की टीम कराएगी बारहवीं के विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं व बारहवीं की परीक्षाएं जून में ली जाएगी। हालांकि दसवीं की परीक्षा लिए जाने की संभावना नहीं है, लेकिन बारहवीं की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब विद्यार्थियों के पास एक माह का समय शेष है। इस एक माह में विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिलों में विषय विशेषज्ञों का पैनल बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि एक माह के दौरान विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी के दौरान होने वाली समस्याओं का समाधान मिल सके। प्रत्येक विषय के शिक्षकों का समूह बनाया जाएगा। सभी का वाट्सएप ग्रुप बनाकर विद्यार्थियों को उस ग्रुप में जोड़ा जाएगा, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा सके। विभाग ने 3 मई तक इस पैनल को तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

प्रत्येक विषय के चार विशेषज्ञ होंगे: जिलेवार बारहवीं के प्रत्येक विषय के लिए विषय विशेषज्ञों का समूह तैयार किया जाएगा। प्रत्येक विषय में कम से कम चार विशेषज्ञों के पैनल बनाएं जाएंगे। वाट्सएप ग्रुप पर विद्यार्थी प्रश्न भेजेंगे, जिनका निराकरण पैनल में शामिल विषय विशेषज्ञ करेंगे।

> भोपाल जिले में 40 शिक्षकों की टीम बनाई गई है। सभी के वाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए हैं। अब सभी विद्यार्थियों के नंबर जोड़े जा रहे हैं।
>
> – **नितिन सक्सेना**, जिला शिक्षा अधिकारी, भोपाल

Badri Gautam

ऑनलाइन क्लासेस बंद करने को पैरेंट्स ने बताया सही, स्टूडेंट्स बोले- 9-11वीं की पढ़ाई होगी प्रभावित

एक से 31 मई तक कक्षाएं बंद रखने के हैं आदेश

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10-12वीं की कक्षाओं को छोड़कर सभी ऑनलाइन कक्षाएं शनिवार से बंद हो जाएंगी। पैरेंट्स इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि यह निर्णय छोटे बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन 9-11वीं के विद्यार्थी इससे अधिक प्रभावित होंगे, क्योंकि उन्हें अगले साल बोर्ड कक्षा में जाना हैं। स्टूडेंट्स व प्राइवेट स्कूल संचालकों का कहना है कि ऑनलाइन कक्षाओं में बच्चे घर बैठकर पढ़ाई करते हैं, ऐसे में कोरोना का खतरा कैसे हो सकता है। डीपीआई आयुक्त जयश्री कियावत ने 10-12वीं को छोड़कर अन्य कक्षाओं को 1 से 31 मई तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, जो सभी सरकारी एवं निजी (सीबीएसई, आइसीएसई, माशिमं या अन्य किसी बोर्ड से संबद्ध) स्कूलों पर लागू होगा।

Badri Gautam

सही निर्णय लिया गया

कोरोना काल में ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने का निर्णय सही है। अस्वस्थ होने से बेहतर है कि बच्चा एक साल ज्यादा पढ़ ले। स्थिति बहुत खराब है और बच्चे टेंशन में है। निर्णय शिक्षकों के लिए भी लाभदायक है।

–नवीन तिवारी, अभिभावक

9वीं व 11वीं को नुकसान

स्कूल बंद हैं। ऑनलाइन क्लास बंद करने का निर्णय छोटी क्लासों के बच्चों के लिए सही है। 9वीं और 11वीं के बच्चे अगले साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे, ऐसे में इस निर्णय से वह अधिक प्रभावित होंगे।

–नित्या द्विवेदी, स्टूडेंट

बच्चे भी डरे हुए हैं

राजधानी के साथ प्रदेशभर में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बच्चे भयभीत हैं और उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग का ऑनलाइन क्लास को एक माह के लिए बंद करने का फैसला सही है।

–प्रबोध पंड्या, महासचिव, पालक महासंघ मप्र

टीचर बच्चों के संपर्क में हैं

शासन ने वर्तमान परिस्थितियों में सही निर्णय लिया है। हमने भी पूरी तरह स्टूडेंट्स से संपर्क नहीं तोड़ा है। बच्चों को हॉलीडे के हिसाब से होमवर्क दिया गया है। टीचर भी अपडेट ले रहे हैं। जिन बच्चों को डाउट होता है, वह टीचर्स से फोन पर संपर्क सकते हैं।

–बाबू थामस, महासचिव, एसोसिएशन ऑफ अनएडेड प्राइवेट स्कूल, मप्र

जारी रखी जा सकेंगी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं

भोपाल। प्रदेश के सरकारी हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों और नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल के बाद भी ली जा सकेंगी। इस संबंध में शुक्रवार को लोक शिक्षण आयुक्त जयश्री कियावत ने आदेश जारी किए हैं। आयुक्त ने पूर्व में जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में सत्र 2020-21 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के निर्देश दिए गए थे। कोरोना संक्रमण के कारण नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

Badri Gautam

स्कूलों में समय से पहले हुई गर्मी की छुट्टियां

नई दिल्ली। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय सहित देश के ज्यादातर स्कूलों में इस बार तय समय से पहले ही गर्मी की छुट्टियां घोषित होनी शुरू हो गई हैं। इन स्कूलों में आनलाइन पढ़ाई जारी रखी गई थी, जिसके लिए शिक्षकों को हर दिन स्कूल आना होता था। इस बीच स्कूलों का सबसे बड़ा संगठन केंद्रीय विद्यालय संगठन ने अपने देश भर के स्कूलों में तीन मई से गर्मी की छुट्टियों का एलान कर दिया है। इनमें यह छुट्टियां 15 मई के बाद होती थी। अब यह स्कूल 21 जून के बाद खोले जाएंगे। (ब्यूरो)

Badri Gautam

सरकारी स्कूलों की 9वीं और 11वीं का परीक्षा परिणाम 15 मई तक होगा घोषित

भोपाल। आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी व समस्त संकुल प्राचार्य हाई स्कूल और हायर सेकेण्डरी को पत्र लिखकर निर्देशित किया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुये शासकीय विद्यालयों की कक्षा 9वीं व 11वीं का वार्षिक परीक्षा परिणाम 15 मई तक घोषित करें। साथ ही परीक्षा परिणाम संबंधी जानकारी को विमर्श पोर्टल पर 20 मई तक दर्ज करें। ज्ञातव्य हो कि पूर्व में परीक्षा परिणाम को 30 अप्रैल तक घोषित करने के निर्देश जारी किये गये थे।

Badri Gautam

शिक्षकों की मौत, नहीं मिला योजना का लाभ

भोपाल। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश के कई शिक्षक, कर्मचारी कोरोना संक्रमण शिकार हुए हैं। ऐसे में कई शिक्षकों की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में मप्र शिक्षक कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए मांग की है कि स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक कर्मचारी अधिकारी दिवंगत हुए हैं उनके आश्रित परिवार को शीघ्र 50 लाख की राशि दी जाए एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में शिथिलीकरण किया जाकर नियुक्ति प्रदान की जाए। शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता एवं भोपाल जिला अध्यक्ष सुभाष सक्सेना ने कहा है कि आज तक प्रदेश में 716 से अधिक शिक्षक कर्मियों का निधन हो चुका है।

Badri Gautam

शिक्षक अवधेश पाठक के निधन पर शोक

रैगांव| इटौरा स्कूल के शिक्षक अवधेश पाठक का कोरोना संक्रमण से निधन हो गया। भाजयुमो नेता वैभव सिंह बघेल बांधी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि हमारे गुरु जी अब हमारे बीच नहीं रहे। शिक्षा के क्षेत्र में वो अपने बेबाक अंदाज एवं विशिष्ट शैली व सरल स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

Badri Gautam

यूजी-पीजी की परीक्षा के लिए 3 मई तक आवेदन कर सकेंगे स्टूडेंट्स

भोपाल। बरकतउल्ला विवि ने यूजी-पीजी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की वार्षिक मुख्य एवं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाई थी। उसमें अब केवल तीन दिन बचे हैं। स्टूडेंट्स सामान्य शुल्क के साथ 3 मई तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा सभी सेमेस्टर एवं ईयर के ओपन बुक एग्जाम के आदेश जारी किए गए हैं। बीयू द्वारा उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में यह संसोधित तारीखें जारी की गई थीं।

बीयू

Badri Gautam

आधार अपलोड कर सीए स्टूडेंट्स भर सकेंगे फॉर्म

रिपोर्टर • IamBhopal
Mobile no. 9827080406

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने चार्टर्ड एकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को राहत देते हुए जरूरी घोषणा की है। इंस्टीट्यूट ने कैंडीडेडट्स को सीए फाउंडेशन कोर्स की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जरूरी 12वीं के एडमिट कार्ड की कॉपी अपलोड करने और एप्लीकेशन व डिक्लेरेशन फॉर्म को अटेस्ट कराने की अनिवार्यता में छूट दी है। कोरोना महामारी के कारण विभिन्न केंद्रीय और राज्य बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित होने की वजह से जिन स्टूडेंट्स को 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, वे इसे बाद में जारी होने के बाद और स्थिति सामान्य होने पर इंस्टीट्यूट के पते पर भेज सकते हैं।

बाद में यहां भेजें...

स्टूडेंट्स 12वीं के एडमिट कार्ड की कॉपी पर अपना सीए फाउंडेशन परीक्षा का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर इसे ईमेल आईडी **foundation_exam-helpline@icai.in** पर मेल भी कर सकते हैं। लॉकडाउन के बीच परीक्षा फॉर्म अटेस्ट कराने में असमर्थ या फोटो और हस्ताक्षर के सिस्टम में न होने की स्थिति में स्टूडेंट्स अब फॉर्म भरते समय अपने आधार कार्ड की कॉपी अपलोड कर एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे।

Badri Gautam

शिक्षक की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए पिता, हो गई मौत

न.सं. | रीवा

शिक्षक पुत्र की मौत का सदमा पिता बर्दाश्त नहीं कर पाए। 24 घंटे के अंदर उन्होंने भी दम तोड़ दिया। मार्तण्ड क्र. 3 में पदस्थ सीएसी राजेश पाण्डेय कोरोना संक्रमित होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। जहां उनकी मौत हो गई थी। बजरंग नगर निवासी राजेश पाण्डेय की मौत से पिता नर्मदा प्रसाद पाण्डेय को गहरा सदमा लगा। इस सदमे ने उनकी जान ले ली। बेटे के चिता की आग ठंडी भी नहीं हो पाई थी कि शहडोल जिले के ग्राम कुआं निवासी नर्मदा पाण्डेय ने भी दम तोड़ दिया। 24 घंटे के अंदर परिवार में दो मौत दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा। गौरतलब है कि शिक्षक राजेश पाण्डेय की ड्यूटी कोरोना वैक्सिनेशन जागरुकता को लेकर रीवा शहर के वार्ड क्र. 3, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21 और 36 में लगाई गई थी। उन्होंने जारी आदेश के तहत अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से की। इसी दौरान वे संक्रमित हो गए और हालत बिगड़ गई। गौरतलब है कि उनका एक बेटा है। जो कक्षा 6 में पढ़ रहा है। उनकी पत्नी अल्का मिश्रा भी शिक्षिका हैं। वे भी गहरे सदमे में हैं। जिला शिक्षा अधिकारी केपी तिवारी, डीपीसी संजय सक्सेना, रमशा प्रभारी डॉ. पीएल मिश्रा, बीईओ आरएल दीपांकर, बीआरसीसी प्रवीण शुक्ला, प्राचार्य रविनारायण वर्मा, उमेश गौतम, राजेन्द्र यादव, अश्वनी सिंह, आराधना पाण्डेय, बालकृष्ण पाण्डेय, रीना मिश्रा, संजय द्विवेदी, संजीव दुबे, जीतेन्द्र चतुर्वेदी, वीरेन्द्र शुक्ला, राजेश सिंह आदि ने शोक व्यक्त किया है।

Badri Gautam

पीएचडी पंजीयन व आरडीसी से वंचितों को राहत

विवि प्रशासन आज से फिर खोलेगा ऑनलाइन आवेदन की लिंक

जागरण, रीवा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने पीएचडी पंजीयन व आरडीसी से वंचित अभ्यर्थियों को एक मौका और दिया है। प्री-पीएचडी कोर्सवर्क परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी 1 से 15 मई तक ऑनलाइन पंजीयन, आवेदन फार्म भर सकेंगे। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन ने विगत सप्ताह सूचना जारी कर दी है। जारी सूचना के अनुसार सत्र 2013-14 एवं 2019-20 में पीएचडी प्रवेश परीक्षा, कोर्सवर्क परीक्षा उपरांत ऐसे अभ्यर्थी आरडीसी हेतु पात्र पाये गए थे परंतु किसी कारणवश पंजीयन आवेदन नहीं कर सके और न ही उनकी आरडीसी हुई। ऐसे अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जारी सूचना में विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि विद्या परिषद की स्थाई समिति के निर्णयानुसार प्रस्तावित आरडीसी में पहले सत्र 2019-20 के अभ्यर्थियों को मौका दिया जायेगा। फिर 2013-14 के अभ्यर्थियों को सम्मलित किया जायेगा।

गौरतलब है कि विश्वविद्यालय ने फरवरी 2019 में प्री-पीएचडी कोर्सवर्क की परीक्षा कराई थी। इस परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय ने गत जुलाई 2020 में जारी किया। उसके बाद 1 नवम्बर से विश्वविद्यालय ने पंजीयन, आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए थे। इस प्रक्रिया में शामिल कई अभ्यर्थियों की आरडीसी मार्च-अप्रैल में हो गई। विश्वविद्यालय ने 8 संकाय के 30 विषयों की आरडीसी कराई, जिसमें तकरीबन 1 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। जबकि अनुमानित दो सैकड़ा के लगभग अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सके। कोरोनाकाल को वजह मानते हुए विश्वविद्यालय ने ऐसे अभ्यर्थियों को पंजीयन, आवेदन का अंतिम अवसर दिया है। विलम्ब शुल्क के साथ अभ्यर्थी 21 मई तक आवेदन कर सकेंगे। तत्पश्चात आवेदन शुल्क की प्रति व अन्य दस्तावेज की हार्डकॉपी अभ्यर्थियों को 25 मई तक विश्वविद्यालय के अकादमिक विभाग में जमा करनी होगी। उक्त प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही अभ्यर्थी आरडीसी में शामिल हो सकेंगे, जो विश्वविद्यालय द्वारा आगामी माह में शीघ्र कराई जा सकती है।

Badri Gautam

दागी पीडब्ल्यूडी अफसर पर सरकार की इनायत : विभागीय पड़ताल के बाद पदोन्नति पर इसलिए भी सवाल क्योंकि लोकायुक्त जांच भी चल रही है अभी

जो अफसर मॉडल स्कूलों में दो करोड़ के घटिया निर्माण का दोषी, उसका प्रमोशन

इंदौर | DB Star

जिले के चारों मॉडल स्कूल में करीब दो करोड़ रुपए के घटिया निर्माण के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। विभागीय जांच में आर्थिक अनियमितता का दोषी मिलने के बाद पीडब्ल्यूडी की पीआईयू (परियोजना क्रियान्वयन इकाई) के जिस तत्कालीन संभागीय परियोजना यंत्री आनंद प्रकाश राणे पर कार्रवाई करना थी, उसे पदोन्नत कर पीआईयू भोपाल का सहायक परियोजना संचालक बना दिया, जबकि लोकायुक्त संगठन इस मामले की जांच ही कर रहा है। इतना ही नहीं, जिन अफसरों ने जांच की, अब वापस उनके पास रिपोर्ट पहुंच गई है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस मामले में दोषी पाए गए बाकी सात अन्य अधिकारी-कर्मचारी पर भी कार्रवाई नहीं हुई है।

आनंद प्रकाश राणे

एक आरटीआई कार्यकर्ता ने शिकायत की थी कि जिले के चारों मॉडल स्कूल (गांधी नगर, देपालपुर, महू, सांवेर का कछालिया) में अमानक और अधूरे निर्माण कर भवन शिक्षा विभाग को हस्तांतरित कर दिए हैं। अमानत निर्माण को लेकर प्रत्येक मॉडल स्कूल में 50 लाख रुपए का घोटाला हुआ। शिकायत वर्ष 2017 में पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव तक पहुंची। तब विभाग की पीआईयू भोपाल के परियोजना संचालक ने इंदौर के जॉइंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर केके लच्छे को जांच के लिए लिखा था। लच्छे की जांच में शिकायत सही पाई गई। विभागीय जांच की यह रिपोर्ट शासन और विभाग के भोपाल मुख्यालय को भी भेजी गई। पीडब्ल्यूडी के अवर सचिव ने 4 जनवरी 2019 को परियोजना संचालक से दोषियों के विरुद्ध आरोप व आधार पत्र मंगवाए थे। इंदौर के अफसरों ने इसमें देरी की तो 1 अप्रैल 2019 को परियोजना संचालक ने अर्द्धशासकीय पत्र भी जारी किया था। तब आरोप व आधार पत्र भोपाल भेज दिए थे, लेकिन सरकार ने कार्रवाई नहीं की।

ये शिकायतें हुई थीं

- इलेक्ट्रिक डॉइंग के आधार पर जिस कमरे में चार पंखे व चार ट्यूब लाइट लगाना थी, वहां दो ट्यूबलाइट व पंखे ही लगाए।
- स्कूलों में चैंबर के ढक्कन अमानक स्तर के थे।
- बिल्डिंग के चारों तरफ सीमेंट-कांक्रीट का बेस बनाना था, लेकिन पैवर्स लगा दिए।
- स्कूल परिसर में लगाए गए कोटा स्टोन की मोटाई कम है।
- स्कूल की कम्प्यूटर, मैथ्स, साइंस लैब में चारों तरफ प्लेटफॉर्म बनाने थे, जो बनाए ही नहीं।

ये 8 अधिकारी-कर्मचारी विभाग की जांच में निकले थे दोषी

विभागीय जांच के बाद जिन आठ लोगों को घटिया क्वालिटी का निर्माण कार्य करवाने के मामले में दोषी पाया था, उसमें तत्कालीन संभागीय परियोजना यंत्री आनंद प्रकाश राणे, संभागीय परियोजना यंत्री योगेंद्र बागोले, परियोजना यंत्री राजेंद्र महाजन, प्रभारी सहायक परियोजना यंत्री जयदेव गौतम, उप परियोजना यंत्री मंजू दांगे, उप परियोजना यंत्री आलोक जोशी, उप परियोजना यंत्री अतुल भटनागर, उप परियोजना यंत्री मंडलोई शामिल हैं। अब आनंद प्रकाश राणे को पदोन्नत कर सहायक परियोजना संचालक पीआईयू भोपाल में पदस्थ कर दिया, जबकि उसके खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है।

नियम कहता है...

दोषी को नहीं कर सकते पदोन्नत

सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आर्थिक अनियमितता से संबंधित शिकायत होती है और वह जांच में सही पाई जाती है तो उसे पदोन्नति जैसे लाभ नहीं दिए हैं। इसके बावजूद राणे को पदोन्नत कर दिया।

मुझे तो याद ही नहीं कि मामला क्या है

इस मामले को मैं तो भूल गया हूं। मुझे याद नहीं मेरे खिलाफ क्या मामला है।
आनंद राणे, सहायक परियोजना संचालक पीआईयू भोपाल

मैंने सारे दस्तावेज भेजे थे लोकायुक्त को

मुझसे जो जानकारी व दस्तावेज मांगे गए थे, वो मैंने पूरे लोकायुक्त संगठन को पहुंचा दिए थे। वहीं जांच चल रही है। आगे की कार्रवाई उन्हें ही करना है।
एके चटर्जी, तत्कालीन संभागीय परियोजना यंत्री पीआईयू इंदौर (अब भोपाल में पदस्थ)

जांच रिपोर्ट शासन को सौंपी

जो शिकायतें मिली थीं, उनमें से काफी हद तक सही पाई गई थी। मैंने जांच कर रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। इसके बाद शासन की तरफ से ही आरोप तय होना थे।
केके लच्छे, तत्कालीन जांच अधिकारी और जॉइंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर पीआईयू पीडब्ल्यूडी

Badnawar.com

योजनाओं का लाभ पाने आधार कार्ड जरूरी

स्नातक कक्षाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए निर्देश जारी होने की सम्भावना

जागरण, रीवा। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को आधार कार्ड अनिवार्य किया जा सकता है। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रवेश के लिए पहले से ही आधार अनिवार्य कर रखा है। अब विभाग की सभी योजनाओं का लाभ पाने वाले विद्यार्थी के पास आधार होना अनिवार्य करने की तैयारी चल रही है। बताते हैं मुख्यालय स्तर पर इस बाबत कार्यवाही कर ली गई है। वित्त विभाग के निर्देश पर मुख्यालय जल्द ही इस बाबत पत्र जारी कर सकता है।

गौरतलब है कि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय अंतर्गत 71 सरकारी कॉलेज हैं। इन कॉलेज में 75 हजार से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इनमें से कई विद्यार्थी विभाग द्वारा दी गई तरह-तरह की योजनाओं से लाभान्वित होते आ रहे हैं। कई दफा ऐसी शिकायतें भी मिली हैं कि एक विद्यार्थी को दो या दो से अधिक योजनाओं का लाभ मिला है। ऐसे प्रकरणों पर रोकथाम लगाने की कोशिश विभाग द्वारा की जा रही है।

Badri Gautam

सभी योजनाओं में होगा प्रभावी

विभाग की गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना विशेष रूप से कॉलेज में पढ़ रही छात्राओं के लिए चल रही हैं। ऐसे ही विक्रमादित्य योजना, निःशुल्क पुस्तक वितरण योजना समेत कुछ अन्य छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं विद्यार्थियों के हित में सचांलित हैं। विगत वर्ष मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना भी विभाग ने शुरू की है। इन सभी योजनाओं के लिए पात्र विद्यार्थियों को योजना आवेदन के साथ आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

सीआरपीएफ के लिए आवेदन 5 मई तक

सिटी रिपोर्टर| यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (यूपीएससी) ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) के 159 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से जारी है, जो 5 मई को हो जाएगी। कैंडिडेट के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आवेदन करने वाले कैंडिडेट की उम्र 20-25 साल के बीच होनी चाहिए। सिलेक्शन रिटेन एग्जाम, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू से किया जाएगा।

Badri Gautam

मई में होने वाली सीए की परीक्षाएं टलीं

सिटी रिपोर्टर | इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने सीए इंटरमीडिएट और फाइनल की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। पहले सीए फाइनल एग्जाम 21 मई को और सीए इंटरमीडिएट एग्जाम 22 मई को होने वाला था। आईसीएआई के एडिशनल सेक्रेटरी एसके गर्ग ने कहा, इन परीक्षाओं की नई तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। कोरोना की परिस्थितियां सामान्य होने के बाद नई तारीखें तय होंगी।

Badri Gautam

10 तक भरे जाएंगे द्वितीय व तृतीय वर्ष के परीक्षा फार्म

स्नातक की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली के तहत कराने विवि की तैयारी शुरू

जागरण, रीवा

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अगले माह नियमित स्नातक छात्रों की वार्षिक परीक्षा करवा सकता है। विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार परीक्षा के वास्ते तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि विश्वविद्यालय ने आगामी वार्षिक परीक्षा के फार्म विगत मार्च माह में ही जारी कर दिए थे, जिसकी तिथि में अब विश्वविद्यालय द्वारा इजाफा किया गया है। गत दिवस विश्वविद्यालय द्वारा जारी संशोधित सूचना के तहत छात्र अब 10 मई तक ऑनलाइन फार्म भर सकते हैं। उसके बाद विलम्ब शुल्क के साथ 17 मई तक छात्रों को परीक्षा फार्म भरने का समय दिया गया है। बीए, बीएससी, बीकॉम सहित अन्य स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों हेतु यह प्रक्रिया शुरू की गई है।

गौरतलब है कि कोरोनाकाल के चलते सत्र 2020-21 की प्रवेश प्रक्रिया विलम्ब से शुरू हुई। अध्ययन-अध्यापन में भी देरी हुई, लिहाजा अब विश्वविद्यालय भी दो महीने विलम्ब से वार्षिक परीक्षा कराने की योजना बना रहा है। गत 31 मार्च को जारी विभाग की नई गाइडलाइन के मुताबिक आगामी परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली के तहत होंगी। इस परीक्षा में करीब 70 हजार छात्र शामिल हो सकते हैं, जिन्हें घर पर उत्तरपुस्तिका लिखने की सुविधा दी जायेगी। छात्रों को ऑनलाइन प्रश्न-पत्र दिये जायेंगे। प्रश्न पत्र हल करके छात्र उत्तर पुस्तिका नजदीकी संग्रहण केंद्र में जमा करेंगे।

प्रथम वर्ष के छात्र 5 तक फार्म भर सकेंगे

विश्वविद्यालय स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों की वार्षिक परीक्षा जून माह में करवा सकता है। उक्त परीक्षा भी ओपन बुक प्रणाली के तहत ही होगी, जिसके परीक्षा फार्म भी विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए जा चुके हैं। परीक्षा के फार्म ऑनलाइन विश्वविद्यालय ने पिछले माह ही जारी कर दिए थे। जिसके अनुसार विगत 26 अप्रैल तक छात्रों को फार्म भरने का समय दिया गया था। इस अवधि में ऑनलाइन नामांकन न होने की वजह से कई छात्र परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह गए, लिहाजा विश्वविद्यालय ने स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु परीक्षा फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब नियमित स्नातक प्रथम वर्ष के छात्र 5 मई तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकेंगे। इसके उपरांत विलम्ब शुल्क के साथ 10 मई तक परीक्षा फार्म भरने का समय छात्रों को दिया गया है।

दूरवर्ती के परीक्षा फार्म भी 10 तक भरे जाएंगे

वहीं, विश्वविद्यालय ने दूरवर्ती शिक्षा के पाठ्यक्रमों की परीक्षा कराने फार्म जारी किए हैं। विगत दो साल से लंबित परीक्षा के फार्म भरने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल रही, जिसमें विश्वविद्यालय ने वृद्धि कर दी है। अब दूरवर्ती पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने वाले छात्र 10 मई तक ऑनलाइन फार्म भर सकेंगे। जारी सूचना के अनुसार सत्र 2018-19 के पंजीकृत छात्र यह ऑनलाइन परीक्षा फार्म भर सकेंगे। विश्वविद्यालय के दूरवर्ती पाठ्यक्रम में बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएसडब्ल्यू, बीलिब साइंस, पीजीडीसीए, बीजेएमसी के पंजीकृत छात्रों को नियत तिथि तक ऑनलाइन परीक्षा फार्म निर्देशित किया है। परीक्ष फार्म भराने के बाद सम्भव है कि विश्वविद्यालय द्वारा अगले माह तक उक्त परीक्षा का कार्यक्रम भी जारी कर दिया जाये।

Badri Gautam

बीयू के ओपन बुक एग्जाम में शामिल होने के लिए लगेगा तीन सौ रूपए विलंब शुल्क

3 मई तक आवेदन कर सकेंगे यूजी-पीजी के स्टूडेंट

भोपाल (शप्र)। बीयू द्वारा बीबीए होटल मैनेजमेंट प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन सामान्य शुल्क के साथ जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार तीस अप्रैल को समाप्त हो गई। अब एक मई शनिवार से 300 रुपए विलंब शुल्क के साथ तीन मई तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। वहीं, यूजी-पीजी के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष की वार्षिक मुख्य एवं पूरक परीक्षा के आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तीन मई है। ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा सभी सेमेस्टर एवं ईयर के ओपन बुक एग्जाम के आदेश जारी किए गए हैं। बीयू द्वारा उसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदन जमा करने की संशोधित तारीखें जारी की गई थी। शासन के आदेश के अनुसार यूजी-पीजी के सभी सेमेस्टर व ईयर की वार्षिक परीक्षाएं ओपन बुक पैटर्न पर आयोजित की जाना है। इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी विवि को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब विवि द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार अलग-अलग टाइम टेबल जारी किए जाएंगे। बीयू द्वारा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की वार्षिक परीक्षा एवं पूरक परीक्षा के लिए आवेदन की संशोधित तारीख जारी की जा चुकी है। बीयू द्वारा बीबीए होटल मैनेजमेंट प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए आवेदन सामान्य शुल्क के साथ जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार तीस अप्रैल को समाप्त हो गई।

Badri Gautam